नयी सदी में भारत की शिक्षा व्यवस्था – दशा एवं दिशा

जितेन्द्र सिंह गोयल*

आज की शिक्षा में एक ओर ज्ञान का अपार भण्डार बढ़ता चला जा रहा है। सूचना क्रांति के इस युग में विश्व भर की असंख्य जानकारियाँ हमारी मुट्ठी में हैं किंतु इस ज्ञान राशि का हम अपनी संवेदनाओं को जाग्रत करने, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, और समाजिकता का भला करने में कितना उपयोग कर पा रहे हैं? कदाचित् अत्यल्प। वस्तुतः ऐसे ज्ञान की सबसे अधिक नकारात्मक भूमिका तब होती है जब ऐसा ज्ञान हमें हमारे समाज, परंपरा और संस्कृति से अजनबी बना देता है। इसका मूल कारण है व्यावसायिकता का दबाव। आज की शिक्षा प्रणाली में हम बच्चों को प्रारंभिक कक्षा से ही ऐसे प्रोटोटाइप पाठ्यक्रमों में उलझा देते हैं और उनकी पीठ पर किताबों का इतना बड़ा बैग लाद देते हैं कि वे आत्मचिंतन, कल्पनाशक्ति, वैचारिकता या भावनात्मकता की प्रकिया से जुड़ नहीं पाते। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा न होकर एक विदेशी भाषा होना भी इस कार्य में बाधक है। विद्वान साहित्यकार गिरिराज किशोर के शब्दों में रचनात्मकता शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। बच्चों को आरंभ से ही चिंतन की प्रक्रिया सिखाना ज़रूरी है जो बिना रचनात्मकता के संभव नहीं । यह केवल अपनी भाषा में संभव है। भाषा और मनुष्य सहोदर हैं। यह विचार करने की बात है कि आज की पीढ़ी को जिस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है उससे उनकी संवेदना का विकास कंप्यूटर संचालित रोबोट से अधिक क्या हो पा रहा है?

मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य है। वर्तमान परिस्थितियों में सर्वत्र शैक्षिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। क्या कारण है कि पराधीनता के दौर में सन् 1836 ई. में लार्ड मैकाले ने जिस शिक्षा नीति का प्रतिपादन करते हुए हमें हमारी अस्मिता, निजीपन या सम्रगतः संस्कृति से काटने का कार्य किया था आज स्वाधीनता के 63 वर्षों के बाद भी हमारी आज की शिक्षा नीति वही कार्य कर रही है? इसका मूल कारण है कि आज हम अंग्रेज़ी की उपनिवेशवादी व्यवस्था से भले ही अलग हो चुके हों किंतु भूमंडलीकरण के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपनिवेशवादी व्यवस्था के मकड़जाल में बुरी तरह उलझ गए हैं। ब्रिटिश शासकों के लिए शिक्षा उनकी शासन

* *शोध छात्र,* (शिक्षा संकाय), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

व्यवस्था को चलाने का उपकरण मात्र थी पर आज विश्व भर की शिक्षा कदाचित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पाई जाने वाली आजीविका पर निर्भर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भूमंडलीकरण का मूर्त रूप हैं।

> *''भूमंडलीकरण व समाज के हर क्षेत्र में बाजार के संबंधों के फैलाव का शिक्षा के लिए महत्चपूर्ण निहितार्थ है। एक तरफ़ तो हम शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ़ शिक्षा के लिए अपर्याप्त कोष (धन) व 'वैकल्पिक' स्कूलों को सरकारी बढ़ावा, इस ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा का उत्तरदायित्व अब सरकार से हट कर, समुदायों व परिवारों पर आ रहा है। हमें स्कूलों को वस्तु बनने और बाज़ार संबंधी अवधारणाओं के स्कूलों व स्कूल की गुणवत्ता पर लागू होने के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। बढ़ती प्रतियोगिता के वातावरण के चलते, जिसमें स्कूल खिंचते चले जाते हैं और अभिभावकों की महत्वकांक्षाओं के कारण बहुत छोटे बच्चों समेत सभी बच्चों पर ज़बर्दस्त दबाव पड़ता है और उनमें भयंकर तनाव पैदा होता है। इससे उनके वैयक्तिक विकास और सीखने के आनंद में बाधा खड़ी होती है''* (एन.सी.ई.आर.टी., *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*–2005, पृ. 11)

दरअसल शिक्षा का जो पाश्चात्य ढाँचा हमने अपनाया है, उसके दुष्परिणाम भी आने लगे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली का पहला उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव शिशु सब प्रकार से विकसित होकर समाज में उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। शिक्षा के माध्यम से ही सहस्त्रों वर्षो से समाज द्वारा संचित ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, बालक को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही वह अपनी राष्ट्रीय विरासत एवं संस्कृति को ग्रहण करता है तथा शिक्षा के द्वारा ही उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही उसके चरित्र का निर्माण होता है और वही मनुष्य की संज्ञा पाने योग्य हो जाता है। अज्ञान का नाश कर लोक कल्याण की ओर प्रेरित करना भारतीय शिक्षा का मूल उद्देश्य है। पाश्चात्य शिक्षा भौतिक दृष्टि से कहीं अधिक उपयोगितावादी शिक्षा है, वहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य रोटी, कपड़ा, मकान और भौतिक सुख-साधन जुटाना मात्र हो सकता है। जबकि हमारे यहाँ रोटी के साथ-साथ संस्कार (लोक कल्याण) भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है अर्थात् दो दिशाओं की यात्रा एक साथ, एक दिशा आजीविका तो दूसरी वैचारिकता।

अब निर्विवाद रूप से यह तथ्य सामने आया है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो देश की मिट्टी से जुड़ी हो। अतः हमारे देश में भी शिक्षा की देशज प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। विश्व के अधिकांश देश भौतिकता के दुष्परिणामों एवं अपने बढ़ते तनावों से त्रस्त भारत की ओर देख रहे हैं जबकि उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएँ सुलभ हैं।

आज अधिकांश छात्र सिर्फ़ कुछ प्रमाण पत्र प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करने मात्र को ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समझते हैं। साधन सुलभ अभिभावक भी अपने बच्चों को सिर्फ किसी प्रकार प्रमाण पत्रों के दम पर नौकरी दिलवाने के लिए हर प्रकार का रास्ता अपनाने से भी नहीं

हिचकते चाहे वह कैसा भी भ्रष्ट रास्ता क्यों न हो।

वर्तमान में अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय इसलिए नहीं भेजते ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें और उनका संतुलित विकास हो सके बल्कि इसलिए भेजते हैं जिससे वे स्कूली शिक्षा प्राप्त करते ही किसी अच्छे व्यवसाय में प्रवेश पा सकें, यही कारण है कि आज स्कूली कक्षाओं में बच्चे कम परंतु कोचिंग संस्थानों में ज़्यादा दिखाई देते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा की सारी पृष्ठभूमि बदलनी होगी। विद्यालय के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण एवं परिस्थितियों को भी इस प्रकार बनाना होगा कि वह एक बालक की आवश्यकता पूर्ति के साथ-साथ उसके लिए जीवनोपयोगी बन सकें इस महत्वपूर्ण प्रयास में कक्षा-शिक्षण, प्रशिक्षण का स्वरूप, विद्यार्थी-अध्यापक संबंध, शिक्षा में सहयोग आदि चुनौतियों का निराकरण सुनियोजित तरीके से करना होगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस तथाकथित युग में एक नयी अवधारणा सुनने को मिल रही है, वह है- ***''एल. पी. जी.'' अर्थात् ''लिबरलाइज़ेशन (उदारीकरण), प्राइवेटाइज़ेशन (निजीकरण) एवं ग्लोबलाइज़ेशन (वैश्वीकरण-भूमण्लीकरण)।*** ये तीनों तत्व भारत के भाग्य को कितना बदल सकते हैं, यह चिंतनीय है। जिस देश की आधी आबादी सामान्य जीवनयापन करती हो, चालीस करोड़ के लगभग लोग निरक्षर हों, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान विज्ञान की नयी जानकारी को आम लोगों तक पहुँचाने के न तो समुचित संचार-साधन हैं और न ही बाल विकास के सुनियोजित कार्यक्रम जो बच्चों के व्यावहारिक ज्ञान में परिवर्तन कर पाते हों, ऐसे में एल.पी.जी. जैसी बातें स्वत: ही निरर्थक हो जाती हैं।

मौजूदा परिवेश में छात्र, शिक्षक तथा अभिभावक का दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल चुका है। शिक्षा में ह्रास के लिए यद्यपि हमारा समग्र समाज एवं सरकार मुख्य रूप से उत्तरदायी है परंतु शिक्षा के ह्रास में शिक्षक की भूमिका अग्रणी ही मानी जायेगी। आज ऐसे अध्यापकों की कमी नहीं है जो अध्यापन कार्य को पूरी लगन व निष्ठा से नहीं करते और जो कक्षा में पढ़ाने के बजाय ट्यूशनों में अधिक व्यस्त रहते हैं।

यही कारण है कि इन कुंठाओं से ग्रस्त होकर भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन ने 22 मई 1995 को गोहाटी विश्वविद्यालय में अपने दिये गये भाषण में राष्ट्र के नवयुवकों का आह्वान इन शब्दों में किया है- ''देश में सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए छात्र समुदाय को शांतिप्रिय ढंग से एक क्रांति की शुरुआत करनी होगी।''

हम (प्रबन्ध तंत्र, शिक्षक, छात्र, अभिभावक तथा राज्य एवं केंद्रीय सरकार) सभी को चिंतन करना होगा कि वर्तमान परिवेश में हमें क्या करना चाहिए? प्रबंध तंत्र एवं राज्य तथा केंद्रीय सरकार की शिक्षा के विकास में अहम भूमिका होती है। प्रबंध तंत्र का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि उनकी संस्थाओं में सभी शिक्षकों एवं छात्रों को अध्ययन एवं अध्यापन का माहौल मुहैया हुआ है अथवा नहीं। तथा इस संबंध में अध्यापकों एवं छात्रों की कठिनाइयों का निवारण तथा उनको हर प्रकार की शिक्षा संबंधी सुविधा देना प्रबंध तंत्र

एवं सरकार का परम् दायित्व है। साथ ही साथ कक्षाओं में न पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान करना भी प्रबंध तंत्र का नैतिक कर्त्तव्य है। इस संबंध में अच्छे कर्मठ परिश्रमी एवं ईमानदार शिक्षको एवं छात्रों को किसी न किसी रूप में कोई भी प्रेरणा देना वरदान का कार्य करेगा। सभी स्तर के विद्यालयों में एक शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य एवं केंद्रीय सरकार को कड़े से कड़े नियम एवं आचार संहिता को अविलंब लागू करना होगा।

महाविद्यालयों में छात्रों की स्थिति बड़ी ही दयनीय एवं त्रिशंकु की भाँति हो जाती है, जिसका पूरा उत्तरदायित्व अभिभावक पर ही होता है क्योंकि अधिकांश समय वह अभिभावक के साथ रहता है। ऐसे में अभिभावकों का परम् कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चों में एक आदर्श परिवार के चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का समावेश करके ही, उन्हें सस्थाओं में भेजने का साहस करें, अन्यथा घर पर अपने कामकाज़ में हाथ बँटाने का सहारा लें।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका धुरी के समान है। अत: हम सभी को इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्ट व्यवसाय को त्यागना होगा। साथ ही साथ समाज सेवा एवं ज्ञान प्रसार के आदर्श को अपनाना होगा। इस संबंध में शिक्षार्थी की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें भी अपनी मौजूदगी का अहसास कराना होगा तथा पूर्ण चारित्रिक निष्ठा एवं उत्तरदायित्व द्वारा अपने परिवार एवं समाज में अपनी विशिष्ट पहचान से एक अद्वितीय अस्तित्व कायम करना होगा।

शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में डॉ. सम्पूर्णानन्द ने भी कहा है- **'शिक्षा आत्मसाक्षात्कार की कुंजी है।'** इसलिए शिक्षा का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब सभी छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक तथा समग्र समाज शिक्षा के महत्त्व को समझें।

भारतीय समाज में भारत की गौरवमयी संस्कृति एवं नवीन मूल्यों का संघर्ष चरम सीमा पर है, यह इक्कीसवीं सदी भावी भारत का निर्माण भी करेगी चिंता का विषय बना हुआ है। समस्यायँ बहुत हैं। अत: सर्वप्रथम हमें स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना होगा। हम प्राचीन काल से ही चिंतनशील प्राणी रहे हैं। हमें अपने इस गुण को फिर से मज़बूत करना होगा और अपने इसी गुण द्वारा चुनौतियों का सामना करना होगा।

शिक्षा के गिरते स्तर के लिए कोई एक विशेष व्यक्ति दोषी नहीं है। प्राचीन काल में गुरु गुरुकुल आश्रम में शिष्यों को शिक्षा देते थे तब से लेकर वर्तमान में राष्ट्र निर्माता कहलाने वाले शिक्षकों व शिष्यों के बीच में मधुरता की जो दरार पड़ी है, उसका कारण क्या है? शायद शिक्षकों का अपने पवित्र पेशे से भटक जाना। नयी सदी में शिक्षा के गिरते हुए स्तर के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं-

1. शिक्षा की दोषपूर्ण नीति – सन् 1950 में क्रियान्वित किये जाने वाले भारतीय संविधान की 45वीं धारा के माध्यम से यह घोषणा का गई थी कि सरकार 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रयास करेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किये गये। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को वार्षिक सहायता अनुदान दिया गया। किंतु इन सब प्रयासों के बावजूद आज भी हम यह लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाये

हैं। इस निर्धारित लक्ष्य को को न प्राप्त करने का प्रमुख कारण केंद्रीय व राज्य सरकारों की दोषपूर्ण नीति है। सरकार की नीति इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविकता पर आधारित न होकर आदर्शवादिता पर आधारित है। अत: सरकार अपने आदर्श के वशीभूत होकर संविधान से लिखित लक्ष्य की प्रप्ति के लिए सक्रिय कदम न उठाकर अपने उत्तरदायित्व को स्पष्ट कर रही है।

2. समाधान-शिक्षा की निश्चित नीति — इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि सरकार अपनी आदर्शवादी नीति को छोड़कर निश्चित नीति का अनुसरण करे। उसकी सर्वोत्तम नीति यही है कि पहले 6–14 वर्ग के सब बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। जब वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले तभी प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा का रूप प्रदान करने या प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक विद्यालयों में रूपांतरित करने का कार्य आरंभ करे।

3. शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन — भारत में शिक्षा का प्रशासन दोषपूर्ण है। भारत की लगभग समस्त स्थानीय संस्थाएँ अपनी अयोग्यता, अकर्मण्यता एवं अकिंचनता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे या तो ऋण–ग्रस्त हैं या दरिद्रता के दावानल से प्रज्जवलित होकर क्षीणकाय बन चुकी हैं। ऐसी संस्थाओं से प्राथमिक शिक्षा के सुप्रशासन की बात सोचना व्यर्थ है।

शिक्षा के दोषपूर्ण प्रशासन का एक अन्य कारण है कि स्थानीय संस्थाओं के सदस्य अपनी लोकप्रियता में वृद्धि करने के लिए निर्वाचित क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तो कर देते हैं पर धनाभाव के कारण विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रशासन में शिथिलता एवं अनियमितता का प्रवेश हो जाना स्वाभाविक ही है।

नयी सदी में हमारे सामने और भी बहुत सी समस्याएँ हैं, जैसे—

- प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव
- विद्यालयों का अभाव
- राजनीतिक कठिनाइयाँ
- शिक्षकों का अपने पवित्र पेशे से भटक जाना
- प्रेरणा का अभाव
- अपव्यय एवं अवरोधन
- छात्रों की अनुशासनहीनता

शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए इन समस्याओं का निराकरण करना अति आवश्यक है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ सुझाव—

- शिक्षा की निश्चित नीति
- शिक्षा के प्रशासन में सुधार
- पाठ्यक्रम में सुधार
- प्रशिक्षित अध्यापकों की पूर्ति
- विद्यालय भवनों का निर्माण
- सरकार का शिक्षा पर पूर्ण ध्यान
- सहायक सेवाएँ (जैसे- नि:शुल्क मध्यांतर भोजन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, लेखन साम्रगी, ड्रेस का वितरण आदि)
- परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि।

पिछली कुछ सदियों से हमने अपने ज्ञान दर्शन अध्ययन और आध्यात्मिक चिंतन को भुला दिया है। पतंजलि एवं पाणिनि जैसे ऋषियों–मनीषियों को योग विद्या और वैज्ञानिक चिंतन का कितना गहन ज्ञान था, यह हमें तब मालूम पड़ता है, जब

उसकी जानकारी लेने यूरोप और अमेरिका जैसे समृद्धिशाली देशों के लोग हमारे पास आते हैं। जिस प्राकृतिक चिकित्सा और देशी दवाओं पर कभी भारत का एकाधिकार था, उसे भी हमने आधुनिकता की चकाचौंध एवं अंग्रेज़ियत के वशीभूत होकर विस्मृत कर दिया है और अब तो स्थिति यहाँ तक आ गयी कि इसकी जानकारी देने लोग बाहर से आ रहे हैं। नीम, हल्दी, बासमती चावल इत्यादि के पेटेन्ट अमेरिका और जापान जैसे देशों में बन रहे हैं। अत: प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर देशज शिक्षा प्रणाली को अपनाना अब आवश्यक हो गया है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली की कापियाँ गिनाते हुए तो हमने पिछले 65 वर्ष व्यर्थ ही गवाँ दिये और प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपने मूल्यों को खोया तथा अभी तक किसी भी सर्वमान्य विकल्प तक हम नहीं पहुँच सके हैं।

अब हमें जागना होगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण का सामना करने हेतु अपनी कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी। इसलिए मौजूदा शैक्षिक एवं परीक्षा प्रणाली में बदलाव, के साथ ही पर्यावरण और मूल्य-आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की महती आवश्यकता है। पिछले 65 वर्षों में हमने पाने की अपेक्षा खोया ज़्यादा है।

शिक्षा, शिक्षक और समाज जैसे-तीन पक्ष किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं और समाज तथा संस्कृति के मूल्यों को स्थापित भी कर सकते हैं। इससे हम, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नये कलेवर के साथ नये क्षितिज तक पहुँचाकर भूमण्डलीकरण के भँवर में भटकती भारतीय शिक्षा को नया आयाम दे सकते हैं।

संदर्भ

गुप्ता, एस.पी. और अलका गुप्ता. 2008. *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ.* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद

कुमार, निरंजन. 2010. 'आभाओं से घिरी उच्च शिक्षा'. *दैनिक जागरण* (इलाहाबाद), फरवरी 04

पांडे, रामशकल और करुणाशंकर मिश्र. 2005. *भारतीय शिक्षा की सम-सामयिक समस्याएँ,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

एन.सी.ई.आर.टी. 2008. *भारत में विद्यालयी शिक्षा – वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएँ.* श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली

भारत सरकार. 1985. *शिक्षा की चुनौती – नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य.* शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्. 2009-10. *रिसर्च एब्स्ट्रेक्स.* लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सियाराम. 2011. *नयी सदी में भारत-चुनौतियाँ एवं समाधान के उपाय.* ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली

शर्मा, आर.ए. 2006. *भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास.* आर. लाल बुक डिपो, मेरठ

http://www.ugc.ac.in/ugcpdf/740315_12FYP.pdf

http://www.ugc.ac.in/ugcpdf/208844_HEglance2012.pdf